

Weekly Current Affair

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स



(24-30 April 2022)

Weekly Current Affairs

Table of Contents

International Relations

National.....

State.....

Defence.....

Science & Technology

Environment

Sports.....

Awards And Honours.....

Appointment/ Resignation.....

Personality

Important Days.....



Weekly Current Affairs

International Relations

2030 तक विश्व हर साल कम से कम 560 जलवायु आपदाओं का सामना करेगा: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2030 तक विश्व हर साल लगभग 560 आपदाओं का सामना करेगा।



प्रमुख बिंदु

- पिछले 20 वर्षों में दुनिया ने हर साल 350-500 मध्यम से बड़े पैमाने पर आपदाओं का अनुभव किया है।
- यह पिछले तीन दशकों की तुलना में पांच गुना अधिक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी **वैश्विक आकलन रिपोर्ट (GAR 2022)** के अनुसार।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDRR)** ने मई, 2022 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक मंच से पहले रिपोर्ट जारी की।
- जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन के कारण आपदा आवृत्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
- चूंकि सैंड्राई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा चल रही है, यह रिपोर्ट एक जागृत कॉल होनी चाहिए कि देशों को बढ़ती आपदाओं को रोकने के लिए फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं में कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है।
- 2030 तक जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभावों के कारण अतिरिक्त 37.6 मिलियन लोगों के अत्यधिक गरीबी की स्थिति में रहने का अनुमान है।
- उच्च आपदा जोखिम का सामना करने वाले अधिकांश देश भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के उच्चतम हिस्से वाले देशों में से हैं।
- इनमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र से फिलीपींस, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।

स्रोत: DTE



यूक्रेन विवाद के बाद से भारत की रूसी कूड खरीद 2021 की खरीद से दोगुनी

चर्चा में क्यों?

- भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से दो महीनों में रूस से दोगुने से अधिक कच्चे तेल की खरीद की है, जैसा कि उसने पूरे 2021 में किया था।
- भारत ने ऐसे समय में रूस से तेल आयात बढ़ाने के लिए रियायती कीमतों का लाभ उठाया है जब वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं।



प्रमुख बिंदु

- अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसका 80% से अधिक आयात किया जाता है।
- लेकिन एक कमोडिटी रिसर्च ग्रुप केप्लर के अनुसार, 2021 में, इसके कुल तेल आयात (यूराल कूड के 12 मिलियन बैरल) का लगभग 2% ही रूस से आया था।
- लेकिन अब तक, केप्लर के अनुसार, मार्च, अप्रैल, मई और जून को कवर करने वाले भारत के लिए किए गए यूराल तेल अनुबंधों की मात्रा - लगभग 26 मिलियन बैरल - पूरे 2021 के दौरान खरीदी गई मात्रा से अधिक है।
- यूक्रेन पर इसके आक्रमण के बाद, रूस के यूराल कच्चे तेल के लिए अब कम खरीदार हैं, कुछ विदेशी सरकारों और कंपनियों ने रूसी ऊर्जा निर्यात से दूर रहने का फैसला किया है, और इसकी कीमत गिर गई है।

स्रोत: BBC

यूरोपीय संघ (EU) डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की कि वे **डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)** पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंच गए हैं।



प्रमुख बिंदु

- **डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)** बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना और अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और उनके मौलिक



Weekly Current Affairs

अधिकारों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने" के लिए मजबूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है।

- यह तकनीकी कंपनियों द्वारा स्व-नियमन के युग को समाप्त करने का प्रयास करता है, और 'इस सिद्धांत को व्यावहारिक प्रभाव देता है कि जो अवैध ऑफ़लाइन है, वह ऑनलाइन अवैध होना चाहिए'।
- यह "सरल वेबसाइटों से लेकर इंटरनेट अवसंरचना सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक, ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी" पर लागू होगा।

पृष्ठभूमि:

- आयोग ने **डिजिटल बाजार अधिनियम** के प्रस्ताव के साथ 15 दिसंबर 2020 को **डिजिटल सेवा अधिनियम** पर अपना प्रस्ताव रखा, जिस पर 22 मार्च 2022 को यूरोपीय संसद और परिषद एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचे।
- इन पर राजनीतिक समझौते यूरोपीय संघ में एक सुरक्षित, खुला और निष्पक्ष ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दो फाइलें एक साथ काम करेंगी।

नोट: भारत में, इसी तरह के मुद्दे पर एक विधेयक (डेटा संरक्षण विधेयक 2019) संसद में लंबित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर हाट दो साल बाद खुला

चर्चा में क्यों?

- मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर **बॉर्डर हाट** दो साल के अंतराल के बाद खोला गया।



प्रमुख बिंदु

- मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में बलात और बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के दलोरा में लौवाघर के बीच बॉर्डर हाट खोलने का निर्णय संयुक्त बॉर्डर हाट प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया था।
- वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश में सात स्थापित बॉर्डर हाट हैं और नौ और नए बॉर्डर हाट पाइपलाइन में हैं।
- **बॉर्डर हाट** सीमा के दोनों ओर के स्थानीय निवासियों को स्थानीय उत्पादों का व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं।

नोट: 2021 तक, भारत के पास केवल 4 बिमस्टेक (BIMSTEC) पड़ोसियों, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ बॉर्डर हाट हैं।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर



महामारी के बावजूद विश्व सैन्य खर्च अब तक के उच्चतम स्तर पर: SIPRI

चर्चा में क्यों?

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार, महामारी के आर्थिक नतीजों के बावजूद 2021 में विश्व सैन्य खर्च में वृद्धि जारी रही, जो 2.1 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।



प्रमुख बिंदु

- 2021 में पांच सबसे बड़े खर्च करने वाले अमेरिका, चीन, भारत, UK और रूस थे, जो कुल खर्च का 62% हिस्सा थे।
- भारत का 76.6 अरब डॉलर का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यह 2020 से 0.9% और 2012 से 33% अधिक था।
- स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के अभियान में, 2021 के भारतीय सैन्य बजट में पूंजी परिव्यय का 64% घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया था।
- 2021 में तेज आर्थिक सुधार के परिणामस्वरूप, विश्व सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में वैश्विक विश्व सैन्य व्यय 0.1 प्रतिशत अंक गिर गया, जो 2020 में 2.3% से 2021 में 2.2% हो गया।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के बारे में:

- SIPRI स्टॉकहोम में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है।
- यह 1966 में स्थापित किया गया था और सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ-साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

स्रोत: द हिंदू



एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने ट्विटर को करीब 44 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया है।



प्रमुख बिंदु

- सौदा, जिसे सर्वसम्मति से ट्विटर के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, इस साल पूरा होने की उम्मीद है। इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिए जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा।

ट्विटर के बारे में:

- ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, जिस पर उपयोगकर्ता "ट्वीट्स" नामक संदेशों को पोस्ट और इंटरैक्ट करते हैं।
- **CEO:** पराग अग्रवाल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विश्व के सबसे गरीब देशों को स्वास्थ्य केंद्रों में जल, स्वच्छता के लिए सालाना 600 मिलियन डॉलर की जरूरत: वाटरएड

चर्चा में क्यों?

- एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक कुछ सबसे गरीब देशों में स्वास्थ्य केंद्रों में जल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए सालाना लगभग 600 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन **वाटरएड** का विश्लेषण लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक नवीनतम शोध पत्र पर आधारित है, जिसमें 46 **सबसे कम विकसित देशों (LDC)** में स्वास्थ्य सुविधाओं में जल, सफाई और स्वच्छता की कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- दुनिया के सबसे गरीब देशों में हर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में जल और स्वच्छता के प्रावधान को प्राप्त करने के लिए 2021 से 2030 तक लगभग 6.5-9.6 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- **जल, सफाई और स्वच्छता (WASH)** तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए घरेलू सार्वजनिक संसाधन वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- LDC में आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी जल सेवाओं की कमी है और 60 प्रतिशत में स्वच्छता सेवाएं नहीं हैं।
- विश्व में चार स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक में बुनियादी जल सेवाओं की कमी है, जैसा कि WHO और UNICEF द्वारा जल आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन कहा गया है।
- जल और स्वच्छता के लिए वैश्विक वित्त पोषण का लगभग 75 प्रतिशत अब ऋण के रूप में है।
- वाटरएड दुनिया के सबसे अमीर देशों से आह्वान कर रहा है, जिसमें G7 भी शामिल है, जिसकी जून 2022 में जर्मनी में बैठक होगी, ताकि कुछ सबसे गरीब देशों में स्वास्थ्य केंद्रों को जीवन रक्षक जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2030 तक 600 मिलियन डॉलर वार्षिक फंडिंग गैप को पूरा किया जा सके।

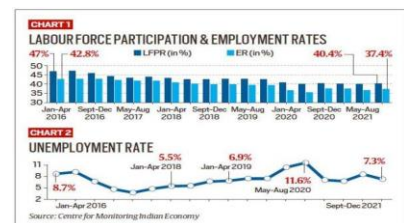
स्रोत: DT

National

भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR)

चर्चा में क्यों?

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डेटा से पता चलता है कि **भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR)** 2016 में पहले से कम 47% से गिरकर सिर्फ 40% रह गई है।



प्रमुख बिंदु

- इससे न केवल यह पता चलता है कि कामकाजी आयु वर्ग (15 वर्ष और उससे अधिक) में भारत की आधी से अधिक आबादी नौकरी के बाजार से बाहर बैठने का फैसला कर रही है, बल्कि यह भी है कि लोगों का यह अनुपात बढ़ रहा है।
- LFPR अनिवार्य रूप से काम करने की उम्र (15 वर्ष या उससे अधिक) आबादी का प्रतिशत है जो नौकरी मांग रहा है; यह एक अर्थव्यवस्था में नौकरियों के लिए "मांग" का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें वे लोग शामिल हैं जो कार्यरत हैं और जो बेरोजगार हैं।
- बेरोजगारी दर (UER) श्रम बल के अनुपात के रूप में बेरोजगारों (श्रेणी 2) की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है।

भारत में LFPR का महत्व:

- आमतौर पर, यह उम्मीद की जाती है कि LFPR काफी हद तक स्थिर रहेगा। जैसे, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कोई भी विश्लेषण केवल UER को देखकर किया जा सकता है।
- लेकिन, भारत में, LFPR न केवल दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है, बल्कि गिर भी रहा है। यह, बदले में, UER को प्रभावित करता है क्योंकि LFPR वह आधार (हर) है जिस पर UER की गणना की जाती है।
- दुनिया भर में, LFPR लगभग 60% है। भारत में, यह पिछले 10 वर्षों में फिसल रहा है और 2016 में 47% से घटकर दिसंबर 2021 तक केवल 40% रह गया।

सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल:

- स्टार्ट अप इंडिया योजना
- आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन (SMILE)
- PM-दक्ष
- मनरेगा
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PM-स्वनिधि योजना दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM-स्वनिधि)** को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।



प्रमुख बिंदु:

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM-स्वनिधि) के बारे में:

- इस योजना के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है।
- इस योजना में 5,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए ऋण की सुविधा की परिकल्पना की गई थी।
- आज की मंजूरी से ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है जिसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
- रेहड़ी-पटरी वालों के लिये कैश-बैंक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बजट को भी बढ़ाया गया है।
- आशा की जाती है कि इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
- PM-स्वनिधि के अंतर्गत, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये।
- यह योजना जून 2020 में शुरू हुई थी।

स्रोत: PIB

भारत की तकनीकी ताकत का दोहन करने के लिए CSIR और आईक्रिएट (iCreate) के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात सरकार के प्रमुख प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर - आईक्रिएट (iCreate) (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन के तहत, CSIR और आईक्रिएट देश में उद्यमियों और नवोन्मेषकों के लिए संयुक्त संसाधन उपलब्ध करके भरोसेमंद तकनीकी स्टार्ट-अप के लिए एक सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित करने का विचार है।



- ऐसे स्टार्ट-अप CSIR के उपकरण, सुविधाओं और वैज्ञानिक मानवशक्ति का उपयोग करेंगे।
- CSIR उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा सहायता प्रदान करेगा और भारत के अभिनव स्टार्ट-अप को वित्तीय रूप से समर्थन देने के तरीकों का पता लगाएगा।

आईक्रिएट (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी) के बारे में:

- यह गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है और तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्ट-अप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है।
- अब तक इसने 412 से अधिक नवाचारों और उच्च स्तर के 30 पेटेंट से अधिक, एंटरप्रेन्योर फ्रस्ट मॉडल को समर्थन दिया है, जो उन्हें परामर्शकर्ता, बाजार और धन से जोड़ता है।
- यह भारत में सिस्को की सबसे बड़ी नवाचार प्रयोगशाला का स्थान है और अमेरिका, इजराइल एवं अन्य देशों के प्रमुख संस्थानों के साथ इसकी साझेदारी है।

भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:

- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है।
- भारत में लगभग 20,000 स्टार्टअप; इनमें से लगभग 4,750 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप हैं।

अन्य संबंधित पहल:

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम
- मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज

स्रोत: PIB

केंद्र ने केंद्रीय विद्यालयों में MP कोटा समाप्त किया, प्रवेश दिशानिर्देशों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने **केन्द्रीय विद्यालयों (KV)** में प्रवेश के लिए विवेकाधीन संसद सदस्य (MP) कोटा खत्म कर दिया है, और संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए हैं।



प्रमुख बिंदु

- KVS विशेष व्यवस्था प्रवेश योजना, या MP कोटा के तहत, एक संसद सदस्य को कक्षा 1 से 9 में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश करने की शक्ति थी।
- सांसद के अलावा अन्य कोटा, KVS ने अन्य आरक्षणों को भी हटा दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चे, सांसदों और सेवानिवृत्त KV कर्मचारियों के बच्चों और आश्रित पोते, और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटा शामिल हैं।



- नए कोटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स जैसे समूह B और C केंद्रीय पुलिस संगठनों के बच्चों के लिए 50 सीटें शामिल हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा, सीमा के लिए तैनात किया गया है।
- इसके अलावा, KVS ने प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर PM केयर्स योजना के तहत शामिल बच्चों को भी शामिल किया है।

स्रोत: HT

कोवैक्सिन, कॉर्बेवैक्स को 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली

चर्चा में क्यों?

- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) 5-12 आयु वर्ग के लोगों के लिए कॉर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA), 6-12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सिन और 12 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ZyCoV-D प्रदान करता है।



प्रमुख बिंदु

- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने भारत बायोटेक के COVID वैक्सीन कोवैक्सिन को 6-12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया है।
- इसके अलावा DCGI ने 5-12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण भी प्रदान किया।
- कैडिला हेल्थ के ZyCoV-D को 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है।

नोट: विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 24 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया जा रहा है। 2022 का विषय 'सभी के लिए लंबा जीवन' है।

स्रोत: ET

रायसीना डायलॉग 2022

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी **रायसीना डायलॉग 2022** के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुये, जिसमें यूरोपीय कमीशन की



अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रमुख वक्तव्य दिया था।

प्रमुख बिंदु

- रायसीना डायलॉग 2022 का सातवां संस्करण 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जा रहा है।
- **रायसीना डायलॉग 2022 का विषय** "टेरा नोवा: इम्पैसियनड, इंपेशेंट, एंड इम्पेरिल्ड" है।
- संवाद के छह व्यापक विषयगत स्तंभ हैं जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, वाटर कौकस, हरित ट्रांजीशन प्राप्त करना शामिल है।

रायसीना डायलॉग के बारे में:

- यह नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय सम्मेलन है।
- 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, यह सम्मेलन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है।
- सम्मेलन की मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक स्वतंत्र थिंक टैंक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

भारत, फिर से, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर 'विशेष चिंता का देश': अमेरिकी आयोग

चर्चा में क्यों?

- अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF) ने लगातार तीसरे वर्ष सिफारिश की कि भारत को 2021 में 'विशेष चिंता का देश' (CPC) नामित किया जाए, यानी धार्मिक स्वतंत्रता मानदंडों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सरकारों की श्रेणी।



प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2021 में "काफी खराब" हो गई थी।
- भारत पर रिपोर्ट अनुभाग में कहा गया है कि सरकार ने "महत्वपूर्ण आवाजों का दमन किया", विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और उन पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति।



Weekly Current Affairs

- इसमें कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुरान परवेज की गिरफ्तारी और जुलाई 2021 में ऑक्टोजेरियन फादर स्टेन स्वामी की मौत का जिक्र है, जिसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।
- रिपोर्ट गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के सामने आने वाली चुनौतियों को छूती है, खासकर विदेशी फंडिंग के संबंध में। यह धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर भी प्रकाश डालती है।

नोट:

- CPC पदनाम के लिए अनुशंसित अन्य देश थे: अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम।
- USCIRF ने सिफारिश की कि विदेश विभाग म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को CPC के रूप में फिर से नामित करे।

भारत में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारत में धर्म की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
- इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF) के बारे में:

- USCIRF एक अमेरिकी संघीय सरकार का आयोग है जिसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया है।
- स्थापना:** 28 अक्टूबर 1998
- मुख्यालय:** वाशिंगटन, DC

स्रोत: द हिंदू

आहार 2022

चर्चा में क्यों?

- कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) भारत व्यापार संवर्धन संगठन



(ITPO) के सहयोग से एशिया के सबसे बड़े B2B अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले **आहार 2022** के 36वें संस्करण का सह-आयोजन कर रहा है।

- यह 26-30 अप्रैल, 2022 तक प्रगति मैदान (नई दिल्ली) में आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- 80 से अधिक निर्यातक कृषि उत्पादों के विभिन्न खंड बनाते हैं, जिसमें GI उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक, फ्रोजेन खाद्य उत्पाद, मोटे अनाज आदि शामिल हैं।

नोट:

- GI रजिस्ट्री द्वारा GI के रूप में 150 से अधिक खाद्य तथा कृषि उत्पादों को पंजीकृत किया गया है जिसमें से मार्च, 2022 तक 123 GI उत्पाद APEDA के वर्ग के तहत आते हैं।
- DGCI&S डाटा के अनुसार, कृषि उत्पादों में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 19.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और वह 50.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं।
- यह वृद्धि दर उल्लेखनीय है क्योंकि यह वित्त वर्ष 2020-21 में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अर्जित 41.87 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त है।

स्रोत: ET

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' अभियान का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक 'किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है।



प्रमुख बिंदु

- सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र द्वारा फसल बीमा पर आयोजित देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ करेंगे।
- प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेला भी आयोजित किया जा रहा है।



- यह अभियान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत उपलब्धियों और गतिविधियों पर भी प्रकाश डालता है।

नोट: 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' अभियान के अंग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइसेज (PMFME) योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अखरोट के प्रसंस्करण तथा मूल्यसंवर्धन पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) आधारित कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइसेज (PMFME) योजना के बारे में:

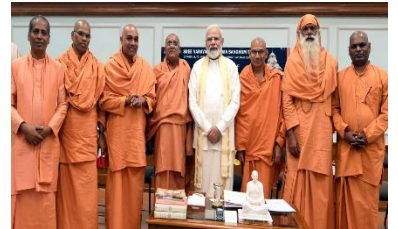
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित वर्ग में मौजूदा वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना तथा इस सेक्टर के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहन देना और किसान उत्पादक संगठनों, स्वसहायता समूहों व उत्पादक सहकारिताओं सहित पूरी मूल्य श्रृंखला को समर्थन देना है।
- इस सम्बंध में 2020-21 से 2024-25 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिये 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे मदद मिलेगी, जिसमें वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक मदद शामिल है। यह मदद मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये दी जायेगी।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

प्रधानमंत्री मोदी शिवगिरी तीर्थदानम् की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोहों के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुये

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7, लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी तीर्थदानम् की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोहों के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुये।
- उन्होंने वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोहों का लोगो भी जारी किया।



प्रमुख बिंदु

- शिवगिरी तीर्थदानम् और ब्रह्म विद्यालय, दोनों महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी समृद्ध किया।
- उन्होंने जातिवाद के नाम पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यावहारिक लड़ाई लड़ी।
- शिवगिरी का ब्रह्म विद्यालय इसी परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिये स्थापित किया गया था। ब्रह्म विद्यालय में भारतीय दर्शन पर सात वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसमें श्री नारायण गुरु की कृतियां और दुनिया भर के सभी महत्वपूर्ण धर्मों के ग्रंथ शामिल किये गये हैं।

शिवगिरी तीर्थदानम् के बारे में:

- शिवगिरी केरल में त्रिवेंद्रम जिले के वर्कला नगरपालिका का एक क्षेत्र है।
- यह वर्कला टाउन का एक तीर्थस्थल है जहां श्री नारायण गुरु की समाधि स्थित है।
- उनकी समाधि हर साल शिवगिरी तीर्थयात्रा के दिनों (शिवगिरी तीर्थदानम्) के दौरान 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हजारों भक्तों को आकर्षित करती है।

स्रोत: PIB

प्रधानमंत्री मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बातचीत की।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री मोदी और सुश्री लेयन ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, जलवायु, डिजिटल



Weekly Current Affairs

- प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।
- उन्होंने **मुक्त व्यापार करार और निवेश करार** पर वार्ता के आगामी पुनः प्रारंभ में प्रगति की समीक्षा की।
 - उन्होंने **भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद** की स्थापना की घोषणा की।
 - दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत पर बढ़ते नीतिगत अभिसरण को नोट किया और विश्व व्यापार संगठन (WTO), G-20, अफगानिस्तान और म्यांमार में सहयोग सहित पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
 - नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की संभावनाओं सहित जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में तथ्य:

- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स, बेल्जियम
- **स्थापना:** 1 नवंबर 1993
- **सदस्य देश:** 27
- **यूनाइटेड किंगडम** 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ छोड़ने वाला पहला सदस्य राज्य बन गया।
- 2012 में, यूरोपीय संघ को **नोबेल शांति पुरस्कार** प्रदान किया गया।

स्रोत: PIB

नागर विमानन मंत्रालय ने "योग प्रभा" का आयोजन किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर मेगा 'योग प्रभा' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
- नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने "योग प्रभा" का आयोजन किया।



प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय और इससे संबद्ध संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के 900 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया।



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** ने वर्ष 2014 में **21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY)** के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

नोट: आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अभी लगभग दो महीने की अवधि शेष है, इसलिए 'योग प्रभा' कार्यक्रम योग के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता का सृजन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ लोगों को प्रतिदिन योग में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करेगा।

स्रोत: ET

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।



प्रमुख बिंदु

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते का निष्कर्ष निकालने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है।
- भारत और UK ने इस दशक में द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप-2030 लॉन्च किया।
- भारत और UK सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन में तेजी लाने के लिए एक वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही COP26 में घोषित ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के लिए नई फंडिंग और पूरे भारत में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर संयुक्त कार्य पर सहयोग कर रहे हैं।
- उन्होंने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने पर जोर दिया।



- प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने के UK के फैसले का स्वागत किया।
- दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के साथ-साथ आतंकवाद का मुकाबला करने और हिंसक उग्रवाद और कट्टरपंथ को संबोधित करने पर सहयोग को मजबूत करने के लिए अभियान तेज करने पर भी सहमति व्यक्त की।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

State

पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण के लिए NHLML और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर महत्वाकांक्षी **पर्वतमाला योजना** के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण के लिए NHLML (नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड) और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के गवाह बने।



प्रमुख बिंदु

- यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है जो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय, पर्यावरण के अनुकूल, सुंदर और निर्बाध यात्रा अनुभव की सुविधा प्रदान करेगा। विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, राज्य में कुल 3,232 करोड़ रुपये की लागत से 57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

पर्वतमाला योजना के बारे में:

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषित राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम "पर्वतमाला" को PPP मोड पर लिया जाएगा, जो कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा।



- यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।

स्रोत: PIB

तमिलनाडु ने कुलपतियों के नाम रखने के राज्यपाल की शक्तियों को छीनने के लिए 2 विधेयक पारित किए

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल से राज्य सरकार को अपने कुलपति नियुक्त करने की शक्ति हस्तांतरित करने के लिए 13 विश्वविद्यालयों के कानूनों में संशोधन के लिए दो विधेयक पारित किए।



प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार के पास कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति की कमी का उच्च शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ा है।
- उन्होंने बताया कि गुजरात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य, राज्य सरकार एक खोज समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों से कुलपति नियुक्त कर रही है।
- प्रस्तावित विधेयक इस बात पर जोर देते हैं कि "कुलपति की हर नियुक्ति सरकार द्वारा तीन नामों के पैनल से की जाएगी" एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित।
- UGC (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, "विज़िटर / चांसलर" - ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल - होंगे खोज-सह-चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करें।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत, भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विज़िटर होंगे।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा विज़िटर की हैसियत से नियुक्त किया जाता है।
- कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट: इसके अलावा, केंद्र-राज्य संबंधों को देखने के लिए केंद्र द्वारा 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को वीसी नियुक्त करने की शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए क्योंकि "कार्यों और शक्तियों का टकराव होगा"। उन्नीस राज्यों ने आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अपनी टिप्पणी की पेशकश की।



स्रोत: TOI

शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा

चर्चा में क्यों?

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में घोषणा की कि निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा।



प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- हवाईअड्डा दिसंबर 2022 में उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा।
- यह परियोजना उड़ान (UDAN) (उड़े देश का आम नागरिक) कार्यक्रम के तहत शुरू की गई।
- बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद शिवमोग्गा हवाई अड्डे का कर्नाटक में दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Defence

सरकार ने सैन्य खरीद में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को और बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर संशोधित किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग से रक्षा उपकरण/ सोर्सिंग का आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए और DAC/ रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।
- वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार और वित्तीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इंटीग्रेटी पैक्ट बैंक गारंटी (IPBG) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- इसके अलावा, भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) से बयाना राशि जमा (EMD) की आवश्यकता नहीं है।
- एक ऐसे पारितंत्र की रचना के लिए जो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों, स्टार्टअप और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देता है और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है, **iDEX फ्रेमवर्क** अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- देश के नवोदित स्टार्टअप प्रतिभा पूल को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के दोहरे मंत्रों में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए DAP 2020 की iDEX प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- DAP -2020 की मेक-2 प्रक्रिया, जिसमें प्रोटोटाइप विकास के चरण में उद्योग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण शामिल है, को प्रोटोटाइप के एकल चरण के समग्र परीक्षणों को शामिल करके और प्रत्यायोजित मामलों में प्रारंभिक खरीद के लिए मात्रा की जांच और स्केलिंग के साथ वितरण को सरल बनाया गया है।

स्रोत: इंडिया टुडे

iDEX-प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में **डेफकनेक्ट 2.0** के दौरान **इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) प्राइम** और **छठे डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC 6)** की शुरूआत की।



प्रमुख बिंदु

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) के बारे में:

- इसे अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था।



- इसका उद्देश्य MSME, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता और नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
- **iDEX-प्राइम** का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्टार्ट-अप की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को सहयोग करना है।

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC 6) के बारे में:

- 38 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ DISC 6 लॉन्च किया गया।
- तीनों सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ रक्षा उपक्रमों (DPSU) के अलावा, जो पहले के संस्करणों में भाग ले चुके हैं, DISC 6 नवगठित सात रक्षा कंपनियों, भारतीय तटरक्षक और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कुछ संगठनों की पहली बार भागीदारी का गवाह है।
- प्रॉब्लम स्टेटमेंट का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधुनिक इमेजिंग, सेंसर सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स और स्वायत्त मानव रहित सिस्टम और सुरक्षित संचार से है।
- रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 अगस्त 2018 को बेंगलुरु में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) लॉन्च किया था।

स्वदेशीकरण के संबंध में सरकारी पहल:

- रक्षा औद्योगिक गलियारे
- प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- रक्षा क्षेत्र में नई FDI नीति
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

स्रोत: PIB



Science & Technology

AAI ने गगन आधारित LPV संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) आधारित LPV संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह सफल परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज (ANS) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि और प्रमुख मील का पत्थर है।
- भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है।



प्रमुख बिंदु

- LPV (लोकलाइजेशन परफॉर्मंस विद वर्टिकल गाइडेंस) विमान निर्देशित पद्धति की अनुमति देता है जो जमीन आधारित उड़ान संबंधी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना परिचालन रूप से Cat-IILS के बराबर है। यह सेवा ISRO द्वारा शुरू किए गए GPS और गगन भू-स्थिर उपग्रहों (जीसैट-8, जीसैट-10 और जीसैट-15) की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
- गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली (SBAS) है जिसे AAO और ISRO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- गगन सिस्टम को DGCA ने 2015 में एप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस (APV 1) और एन-रूट (RNP 0.1) संचालन के लिए प्रमाणित किया था।
- भारत (GAGAN-गगन), अमेरिका (WAAS), यूरोप (EGNOS) और जापान (MSAS) नाम से दुनिया में केवल चार अंतरिक्ष-आधारित संवर्धन प्रणालियां उपलब्ध हैं।
- LPV पद्धति से उन हवाई अड्डों पर उतरना संभव हो जाएगा जहां विमान उतारने की महंगी प्रणाली (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) नहीं हैं, इसमें कई छोटे क्षेत्रीय और स्थानीय हवाई अड्डे शामिल हैं।



स्रोत: PIB

भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन जंगल की आग से प्रभावित हो रहा है: स्टडी

चर्चा में क्यों?

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जंगल की आग जो भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।



प्रमुख बिंदु

- सौर संयंत्रों के उत्पादन पर जंगल की आग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण ऊर्जा और वित्तीय नुकसान के इस तरह के विश्लेषण से ग्रिड ऑपरेटरों को बिजली उत्पादन की योजना बनाने और शेड्यूल करने में मदद मिल सकती है, साथ ही बिजली उत्पादन के वितरण, आपूर्ति, सुरक्षा और समग्र स्थिरता में भी मदद मिल सकती है।
- हाल ही में, भारत जैसे विकासशील देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिसके पास पर्याप्त सौर संसाधन हैं। हालांकि, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न बादल, एरोसोल और प्रदूषण जैसे कई कारक सौर विकिरण को सीमित करते हैं जिससे फोटोवोल्टिक और केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन संबंधी समस्याएं होती हैं।

नोट:

- आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES), नैनीताल में शोधकर्ताओं का एक समूह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, और एर्थेंस की राष्ट्रीय वेधशाला (NOA), ग्रीस ने सौर ऊर्जा उत्पादन को कम करने वाले कारकों का पता लगाने की कोशिश की है।
- उन्होंने पाया कि बादलों और एरोसोल के अलावा, जंगल की आग सौर ऊर्जा उत्पादन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्रोत: ET

Environment

संसदीय पैनल ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 में बदलाव का सुझाव दिया



चर्चा में क्यों?

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने **वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021** की समीक्षा के बाद 254 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी।



- इसने कानून के संबंध में कई चिंताओं पर प्रकाश डाला और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से रिपोर्ट में उल्लिखित वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया।

प्रमुख बिंदु

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के बारे में:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन और जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों के शेड्यूल को भी सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न डिग्री की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है।
- अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, अंतिम संशोधन 2006 में किया गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- विधेयक को पेश करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण कारण जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के लिए पिछले कई वर्षों में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को विधायी समर्थन प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता थी, लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि जो 1975 में लागू हुई।
- विधेयक के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि CITES को लागू करके वन्यजीवों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी, टिकाऊ और पता लगाने योग्य है।
- मंत्रालय ने प्रजातियों के शेड्यूलिंग को मूल छह अनुसूचियों से केवल तीन तक सुव्यवस्थित किया है - उन प्रजातियों के लिए अनुसूची I जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा का आनंद लेंगी, उन प्रजातियों के लिए अनुसूची II जो कम सुरक्षा के अधीन होंगी और अनुसूची III जो पौधों को कवर करती है।

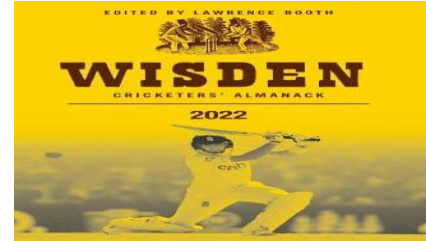


स्रोत: HT

Sports

जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा विजडन के पांच 'क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' 2022 में शामिल

- भारत के कप्तान **रोहित शर्मा** और तेज गेंदबाज **जसप्रीत बुमराह** को अल्मनैक के 2022 संस्करण में विजडन के 'क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' में पांच खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।



- इन दोनों के अलावा, सूची में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और प्रोटियाज महिला स्टार डेन वैन नीकेर्क भी शामिल हैं।

विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के बारे में:

- विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक बोलचाल की भाषा में बाइबिल ऑफ क्रिकेट, यूनाइटेड किंगडम में वार्षिक प्रकाशित होने वाली एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है।

स्रोत: ET

Awards & Honours

भारत ने एक साथ 78,220 झंडे फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

चर्चा में क्यों?

- भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे झंडे फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
- 23 अप्रैल, 2022 को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78 हजार से अधिक तिरंगे झंडे फहराकर **गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड** में नाम दर्ज कराया।



प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव', भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत किया गया था।
- 'अमृत महोत्सव' का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की 164वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था - 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति।
- वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल, 1858 को जगदीशपुर के पास अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया।
- जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा उतारने के बाद राष्ट्र की सेवा में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई।

स्रोत: HT

प्रधानमंत्री मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया।



प्रमुख बिंदु

- लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनकी मृत्यु 6 फरवरी, 2022 को 92 वर्ष की आयु में हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जीते गए अन्य हालिया पुरस्कार:

- भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (2021)
- वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार (2021)
- अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट (2020)

स्रोत: HT



Appointments/Resignations

TCS के कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

- नैसकॉम ने घोषणा की कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- रामानुजम इस भूमिका में भारत में एक्सेंचर की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) के बारे में:

- नैसकॉम एक भारतीय गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है।
- मुख्यालय:** नई दिल्ली
- स्थापना:** 1 मार्च 1988

स्रोत: द हिंदू

इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए

चर्चा में क्यों?

- फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों ने दूसरी बार जीत हासिल की है।



प्रमुख बिंदु

- इमैनुएल मैक्रों ने दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी मरीन ले पेन को हराया।
- दो दशकों में यह पहली बार है जब फ्रांस ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना है।



स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

- प्रख्यात भौतिक विज्ञानी **अजय कुमार सूद** को सरकार का **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)** नियुक्त किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य श्री सूद को के विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है।
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)** के कार्यालय का उद्देश्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित मामलों पर व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण सलाह देना है।

स्रोत: HT

अर्थशास्त्री सुमन के बेरी को NITI आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

- राजीव कुमार के पद से हटने के बाद अर्थशास्त्री **डॉ सुमन के बेरी** को NITI आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सुमन बेरी को NITI आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में 1 मई, 2022 से उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
- सुमन बेरी नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के महानिदेशक थे।
- बेरी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, भारत के सांख्यिकीय आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के बारे में तथ्य:



- **स्थापना:** 1 जनवरी 2015
- **पूर्ववर्ती सरकारी एजेंसी:** योजना आयोग
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **अध्यक्ष:** नरेंद्र मोदी

स्रोत: इंडियन टुडे

Personality

वयोवृद्ध कांग्रेस नेता के शंकरनारायणन का निधन

- विभिन्न राज्यों के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकरनारायणन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उन्होंने छह राज्यों (महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड) में राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने 2001 से 2004 तक एके एंटनी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
- वह त्रिथला, श्रीकंदपुरम, ओट्टापलम और पलक्कड़ के विधानसभा क्षेत्रों से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे।



स्रोत: द हिंदू

प्रसिद्ध लेखक बीनापानी मोहंती का निधन

- प्रख्यात उड़िया लेखक बीनापानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- मोहंती के नाम 100 से अधिक पुस्तकें हैं।
- 2020 में पद्म श्री पाने के अलावा, मोहंती को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओडिशा साहित्य अकादमी द्वारा सरला सम्मान और अतिवादी जगन्नाथ दास सम्मान मिला।



स्रोत: TOI



Important Days

28 अप्रैल, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस



चर्चा में क्यों?

- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रत्येक 28 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2022 सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह सुरक्षित काम और काम से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों के आयामों और परिणामों के बारे में जागरूकता के बारे में चिंतित है; **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH)** को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंडा पर रखने के लिए।
- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस पहली बार 2003 में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** द्वारा मनाया गया था।

स्रोत: un.org

26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व बौद्धिक संपदा दिवस (विश्व IP दिवस) प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।



प्रमुख बिंदु

- विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का **विषय** "IP और युवा: बेहतर भविष्य के लिए नवाचार" है।
- इस दिन की स्थापना **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** द्वारा 2000 में "पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने" के लिए की गई थी।



- 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह उस तारीख से मेल खाता है जिस दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था।

बौद्धिक संपदा:

- बौद्धिक संपदा (IP) दिमाग की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिजाइन; और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र।
- IP कानून में संरक्षित है, उदाहरण के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, जो लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: wipo.int

24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था।
- पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था।

नोट:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू और कश्मीर का दौरा किया।
- प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन किया। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी।
- प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर



25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व मलेरिया दिवस (WMD) हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है और मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देता है।



प्रमुख बिंदु

- विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय "मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें" है।
- विश्व मलेरिया दिवस 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था।

नोट:

- 2020 में, मलेरिया के अनुमानित 241 मिलियन नए मामले सामने आए और 85 देशों में 627000 मलेरिया से संबंधित मौतें हुईं।
- WHO अफ्रीकी क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दो तिहाई से अधिक मौतें हुईं।

स्रोत: who.int

